B.A. II - Sem IV

Part - C - 8

History of West Asia

इजरायल की स्थापना

इजरायल (फिलिस्तीन) एशिया की पश्चिमी छोर पर भू-मध्यसागर तट पर स्थित है। इसकी राजधानी जेरुसलम है लेकिन लंबे समय तक इसकी सीमाएं ठीक तरह निश्चित नहीं थीं। फिलिस्तीन यहूदियों का मूल निवास है। सातवीं शताब्दी में इस भू-भाग पर अरबों का आधिपत्य कायम हो गया। अरबों के बाद फिलिस्तीन पर तुर्कों का अधिकार हो गया और वह ओटोमन साम्राज्य का एक अंग बन गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और फिलिस्तीन पर राष्ट्रसंघ के निर्णय के अनुसार ब्रिटेन का संरक्षण कायम हुआ। 1920 से 1948 ई० तक यहाँ ब्रिटेन का संरक्षण रहा। इस काल में फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों में भीषण संघर्ष हुए। यहूदी फिलिस्तीन को अपना "राष्ट्रीय आवास" बनाना चाहते थे और अरब वहाँ यहूदियों को रहने देना नहीं चाहते थे।

इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। आस्ट्रिया के यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल ने राजनीतिक आंदोलन चलाने में मदद की। सन् 1897 ई० में बासेल में 'विश्व जियोनवादी कांग्रेस' आमंत्रित की गई। इससे अनेक प्रबल राज्य के लिए उत्कट प्रेरणा जाग्रत हुई। प्रथम महायुद्ध के समय फिलिस्तीन का विस्तृत भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में था। अतः नवम्बर 1917 ई० को

ब्रिटिश विदेश मंत्री लॉर्ड बालफोर ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक "राष्ट्रीय-निवास" स्थान की स्थापना के पक्ष में है।

पेरिस शांति सम्मेलन में फिलिस्तीन संरक्षित प्रदेश के रूप में ब्रिटेन को सौंप दिया गया और उसपर यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वह देश का प्रशासन इस प्रकार से करे कि यहूदी राज्य की स्थापना हो सके और साथ ही साथ फिलिस्तीन के सभी निवासियों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों की रक्षा भी हो। इससे उत्साहित होकर लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आकर बसने लगे। यहूदी प्रवासियों की विशाल संख्या में इस निरंतर आगमन से अरब लोग भयभीत हो गए। प्रतिक्रियास्वरूप 1935 ई० से ही अरबों का राष्ट्रीय आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा। उन्होंने सशस्त्र उपद्रवों का आश्रय लिया।

ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पील की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1936 ई० को 'पील आयोग' (Peel Commission) गठित किया। आयोग ने July 1937 ई० में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में आयोग ने स्पष्ट किया कि फिलिस्तीन के अरबों और यहूदियों की राष्ट्रीय आकांक्षा में किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना असंभव है। इसने फिलिस्तीन को अरबों और यहूदियों के

बीच बाँटकर उनके अलग-अलग दो राज्य स्थापन करने की योजना प्रस्तुत की तथा एक क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र के अन्तर्गत रखने का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार आयोग की योजना के अनुसार फिलिस्तीन को तीन भागों में विभाजित किया जाना था — एक यहूदी राज्य, एक अरब राज्य और जाफा से जेरूसलम तक के क्षेत्र को मिलाकर एक ब्रिटिश क्षेत्र।

पील आयोग के प्रस्ताव ने अरब आन्दोलन को गंभीर रूप से भड़का दिया। फलतः पील आयोग की व्यावहारिकता पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठित किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड थे। वुडहेड आयोग ने अक्टूबर 1938 ई० में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया कि विभाजन योजना को कार्यान्वित करना संभव नहीं है अतः सरकार ने फिलिस्तीन विभाजन योजना का परित्याग कर दिया। ब्रिटिश सरकार अब यत्न करने लगी कि अरबों और यहूदियों में कोई ऐसा समझौता हो जाए, जो दोनों पक्षों को मान्य हो। अतः लंदन में गोल-मेज सम्मेलन में दोनों पक्षों को अपना मांग पृथक रूप से रखने के लिए आमंत्रित किया गया। फरवरी-मार्च 1939 ई० में परिषद का अधिवेशन हुआ। ब्रिटिश सरकार के समझौता कराने के सारे प्रयत्न निष्फल हुए और कुछ सप्ताहों के बाद सम्मेलन भंग हो गया।

17 मई, 1939 को ब्रिटेन ने एक श्वेत-

-पत्र प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि दस वर्ष बाद फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाएगा। द्वितीय विश्वयुद्ध के दबाव में ब्रिटेन के लिए अरबों को प्रसन्न करना आवश्यक था, उसने यहूदियों की अप्रसन्नता की विशेष चिंता नहीं की, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका ने यहूदियों को अपना समर्थन प्रदान किया। फिलिस्तीन की समस्या अमेरिकी वैदेशिक नीति का एक प्रमुख तत्व बन गई। अक्टूबर 1945 ई० में राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ब्रिटेन की एटली सरकार से यूरोप में विस्थापित एक लाख यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की अनुमति दे देने का अनुरोध किया।

मई 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक समिति का निर्माण किया तथा घोषणा की कि फिलिस्तीन से ब्रिटिश मैंडेट समाप्त कर दिया जाए और वहाँ अरब तथा यहूदी राज्यों की अलग-अलग स्थापना कर दी जाए। अंग्रेजों ने 1 अगस्त 1948 तक फिलिस्तीन छोड़ने की घोषणा की। अरबों ने यहूदी राज्य की स्थापना का घोर विरोध किया। लेकिन यहूदी अपने ही प्रयत्नों से अपने लिए अलग राज्य की स्थापना के लिए अड़ गए फलतः दोनों जातियों में युद्ध प्रारंभ हो गया। अरब युद्ध में बराबर पराजित होते चले गए। यहूदियों ने बँटवारे में प्राप्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 14 मई, 1948 ई० को ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने फिलिस्तीन छोड़ दिया। यहूदियों ने तेल अवीव में इजरायल नामक नए राज्य की घोषणा कर दी।

15 मई 1948 को अमेरिका तथा 17 मई

1948 को रूस इसे मान्यता प्रदान कर दी। परंतु इसी समय मिस्र, ईराक, सीरिया तथा ट्रांसजोर्डन ने मिलकर यहूदियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी दोनों पक्षों में लड़ाई हुए। इस युद्ध में यहूदी बुरी तरह पराजित हुए। अक्टूबर, 1948 में पुनः युद्ध प्रारंभ हो गया। इस बार यहूदियों को सफलता प्राप्त हुई। अप्रैल 1949 तक सभी मोर्चों पर युद्ध बन्द हो गया। अप्रैल 1950 में इंगलैंड ने यहूदियों के नए राज्य इजरायल को मान्यता प्रदान कर दी। इस प्रकार यहूदियों को अपने उद्देश्य में सफलता मिल गई। मई 1950 में अमेरिका, इंगलैंड तथा फ्रांस ने सम्मिलित रूप से घोषणा की कि वे ~~भविष्य~~ भविष्य में इस प्रदेश में बल प्रयोग का विरोध करेंगे ताकि भविष्य में पुनः अरबों तथा यहूदियों में युद्ध प्रारंभ न हो जाए। लेकिन अरब निरंतर आक्रमण करते रहे और लगातार अरब इजरायल संघर्ष होते रहे।

इस प्रकार यहूदियों ने अपना नया राज्य इजरायल की स्थापना कर ली लेकिन अरबों के साथ उसका लम्बा संघर्ष चलता रहा।

—————— 00 ——————

DSPMU